भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3473
उत्तर देने की तारीख: 16.03.2020

अल्पसंख्यकों में शिक्षा का संवर्धन

†**3473.श्री अनिल फिरोजियाः**
श्री लल्लू सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल्पसंख्यकों में शिक्षा के संवर्धन के लिए चल रही परियोजनाओं को सुदृढ़ किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की है; और
(घ) यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी तथा किन-किन राज्यों में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ख): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं:

i) अल्पसंख्यकों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, योजनाओं के कार्यान्वयन, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक जरूरतों की पहचान, बालिकाओं की शिक्षा और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यक शिक्षा पर राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसीएमई)।
ii) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु इस नीति में असमानता हटाने और समान शैक्षिक अवसरों के लिए विशेष जोर दिया गया है।

iii) निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था अवसंरचना विकास हेतु योजना (आईडीएमआई) अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) की स्कूल अवसंरचना को बढ़ाकर और मजबूत करने के द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा को आसान बनाता है। योजना में परस्पर बालिकाओं, विशेष जरूरतों वाले बच्चों और अल्पसंख्यकों के बीच शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित हेतु शिक्षा सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) से (घ): उच्च शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएसईआर सहित अनेक उच्च शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। 12वीं योजना (2012-17) के पश्चात जैसा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित है, का मुख्य जोर उच्च शिक्षा प्रणाली के समेकन पर है। नई संस्थाओं की स्थापना की बजाय वर्तमान संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के द्वारा विस्तार किया जाना है। इसके अलावा, 'शिक्षा' समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य सरकारें भी विभिन्न पहल कर रही हैं।

*****